यह तो केवल शुरूआत है।
छह महीने की प्रगति रिपोर्ट

THIS IS JUST THE BEGINNING
Six Months' Progress Report

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Government of India

www.chemicals.nic.in
www.fert.nic.in
www.pharmaceuticals.gov.in

Ananth Kumar

Minister for Chemicals & Fertilizers
Government of India

Message

I am happy to present the achievements and initiatives of the Ministry of Chemicals & Fertilizers, comprising of the Departments of Chemicals & Petrochemicals, Fertilizers & Pharmaceuticals of the first six months of the NDA Government.

Under the Inspirational Leadership of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry has been able to launch a number of initiatives and accomplish the twin Mantras of "Good Governance" and "Make in India".

On behalf of the Ministry, I assure of our continued commitment and efforts to achieve the mandate given to us by the people of this country.

श्री अनंत कुमार

रसायन और उर्वरक मंत्री
भारत सरकार

संदेश

मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, उर्वरक विभाग और औषध विभाग के संबंध में एनडीए सरकार की पहले छह महीने की उपलब्धियों और पहलों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व में यह मंत्रालय पहलों का शुभारम्भ करने और ''सुशासन'' एवं ''मेक इन इंडिया'' के दो मंत्रों को पूरा करने में सफल रहा है।

मंत्रालय की ओर से, मैं देश की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को पूरा करने के लिए सतत प्रतिबद्ध और प्रयासरत रहने का आश्वासन देता हूं।

Hansraj G. Ahir

Minister of State for Chemicals & Fertilizers
Government of India

Message

Our Ministry is working as per the directions and guidance issued by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi. As per the policy of "Make in India" we are stressing upon producing more and more fertilizers to make India self reliant in the field. In this direction we are also trying to revive the production of Urea fertilizer which is a substitute for imported gas NAFTA. Through this we can maintain the equilibrium of demand and supply.

Under the guidance of Hon'ble Minister, Ministry is doing its best.

हंसराज गं. अहीर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
भारत सरकार

संदेश

हमारा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार कार्य कर रहा है। "मेक इन इंडिया'' नीति के अनुसार हम उर्वरक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक–से–अधिक उत्पादन पर बल दे रहे हैं। इस दिशा में हम यूरिया उर्वरक के उत्पादन के पुनरोद्धार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि आयातित गैस और नाफ्ता का विकल्प है। इसके जरिये हम मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रख सकते हैं।

माननीय मंत्री के मार्ग दर्शन में मंत्रालय बेहतर कार्य कर रहा है।

Introduction

The Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, has three administrative Departments, namely:-

- Department of Chemicals and Petrochemicals
- Department of Fertilizers
- Department of Pharmaceuticals

Shri Ananth Kumar, Member of Parliament from the Lok Sabha Constituency of Bengaluru South, Karnataka, is the Cabinet Minister

and

Shri Hansraj Gangaram Ahir, Member of Parliament from the Lok Sabha Constituency of Chandrapur, Maharashtra, is the Minister of State.

Shri Jugal Kishore Mohapatra is the Secretary, Dept. of Fertilizers, Shri Surjit Kumar Chaudhary is the Secretary, Dept. of Chemicals & Petrochemicals, and Dr. V K Subburaj is the Secretary, Dept. of Pharmaceuticals.

प्रस्तावना

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन तीन प्रशासनिक विभाग हैं नाम :–

- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
- उर्वरक विभाग
- औषध विभाग

श्री अनंत कुमार, सांसद, लोक सभा, संसदीय क्षेत्र बंगलुरू दक्षिण, कर्नाटक, केन्द्रीय मंत्री हैं

और

श्री हंसराज गंगाराम अहीर, सांसद लोक सभा, संसदीय क्षेत्र चंद्रपुर, महाराष्ट्र राज्य मंत्री हैं।

श्री जुगल किशोर महापात्र, सचिव, उर्वरक विभाग, श्री सुरजीत कुमार चौधरी, सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और श्री वी.के. सुब्बुराज, सचिव, औषध विभाग हैं।

पीसीपीआईआर दहेज, गुजरात
PCPIR Dahej, Gujrat

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS

Draft National Chemical Policy

The Draft National Chemical Policy has been firmed up after extensive consultations with the stakeholders and is under finalization. This policy aims to increase the share of the chemical sector in India's GDP within a decade through various initiatives such as setting up of chemical clusters, building enabling infrastructure, establishing the National Chemical Centre, evolving a chemical management framework, facilitating fast-track project clearances, technology up-gradation, expansion of manufacturing capacities & skill development and identifying and mitigating the problems/ impediments afflicting the industry, especially small and medium sector units. An intensive round of consultation was held recently with the experts of the chemical sector to elicit their views for finalization of the Policy.

Make in India

Fast-Tracking of Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Regions (PCPIRs)

The Ministry has fast-tracked the PCPIRS in 4 States which are estimated to attract investments to the tune of Rs. 7.63 lakh crores. The employment generation in these 4 PCPIR's will be to the tune of 33.96 lakhs. Till now Rs. 1.48

राष्ट्रीय रसायन नीति का प्रारूप

विभिन्न पणधारकों के साथ वृहद चर्चा के उपरांत राष्ट्रीय रसायन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस नीति का लक्ष्य विभिन्न पहलों जैसे रसायन कलस्टर की स्थापना, सक्षम अवसंरचना का निर्माण, राष्ट्रीय रसायन केंद्र की स्थापना, रसायन प्रबंधन रूपरेखा, परियोजनाओं को तेजी से अनापत्ति प्रदान करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विनिर्माण क्षमता एवं कौशल विकास का विस्तार, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारणों/समस्याओं की पहचान एवं उन्हें दूर करना आदि के जरिए एक दशक के भीतर भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रसायन क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। नीति को अंतिम रूप देने के मद्देनजर परामर्श का एक गहन दौर हाल में आयोजित किया गया था जिसमें रसायन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किए।

''मेक इन इंडिया''

पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की प्रगति में तेजी लाना।

मंत्रालय ने चार राज्यों में पीसीपीआईआर की प्रगति में तेजी दिखाई है जिससे 7.63 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आकर्षित होने का अनुमान है इन चारों पीसीपीआईआर में लगभग 33.96 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अब तक 1.48 लाख करोड़ रुपए का निवेश और

lakh crores have been invested and total 2.22 lakh employment generated. After a series of three meetings, a Steering Committee comprising of representatives of concerned Departments, State Governments, Anchor Tenant Companies and Industry Bodies was constituted by the Ministry to chalk out the Road Map and monitor and expedite the implementation of the PCPIRs. As a result of the initiatives two Anchor Tenant Projects namely Opal, Dahej and IOC, Paradeep will be ready for commissioning by March, 2015.

The Ministry is reviewing the PCPIR Policy of 2007 in order to Fast-track implementation and attract investments.

Assam Gas Cracker Project (AGCP)

Hon'ble Ministers reviewed the progress of the implementation of the AGCP. A promise of Assam Accord of 1985 will be fulfilled. AGCP will be an investment of Rs.10,000 crores and will be generating substantial employment in North East. AGCP will be ready for commissioning in June, 2015.

Hindustan Insecticides Limited (HIL)

Hindustan Insecticides Limited
(A Government of India Enterprise)

Hindustan Insecticides Limited (HIL), manufacturing agrochemicals, DDT and also diversified in seed business, has

लगभग 2.22 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित हो चुका है। तीन बैठकों की श्रृंखला के उपरांत संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, एंकर टीनेंट, कंपनियों एवं औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय द्वारा एक स्टीयरिंग समिति गठित की गई है जिसका लक्ष्य पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन की निगरानी एवं तेजी लाने की दिशा में एक रूपरेखा तैयार करना है। इस पहल के फलस्वरूप दहेज पाराद्वीप में दो एंकर टीनेंट परियोजनाएं नामतः ओपल, दहेज एवं आईओसी, पाराद्वीप मार्च, 2015 तक शुरू होने के लिए तैयार है।

मंत्रालय पीसीपीआईआर नीति 2007 की समीक्षा कर रहा है ताकि क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके तथा निवेश आकर्षित हों।

असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)

माननीय मंत्री ने एजीसीपी के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। 1985 के असम समझौते का एक वादा इससे पूरा हो जाएगा। एजीसीपी में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से रोजगार सृजित होने की संभावना है। एजीसीपी जून, 2015 तक प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाएगी।

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि. (एचआईएल)

Hindustan Insecticides Limited
(A Government of India Enterprise)

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि. (एचआईएल) कृषि रसायन डीडीटी का विनिर्माण करती है और बीज व्यापार में भी विविधीकरण कर रही है तथा

been making marginal profits for the last 8 years. For producing and marketing new agrochemicals, HIL is putting up facilities for making Pendimethalin, Glyphosate (Tech), High Purity Dicofol, Suspension Concentrate (SC) Formulation Plant etc., with an assistance of Rs. 15 crore from the Department.

Interaction with major Petrochemical Industry Associations and preparation of roadmap for future

The Hon'ble Ministers (Chemicals & Fertilizers) met representatives of Industry Associations viz. Chemicals & Petrochemicals Manufacturers Association (CPMA), All India Plastics Manufacturers' Association (AIPMA), Organization of Plastics Processors of India (OPPI), Association of Synthetic Fiber Industry (ASFI), All India Flat Tape manufacturers' Association (AIFTMA), and Plastic Machinery Manufacturers Association of India (PMMAI) related to petrochemicals and discussed the issues affecting the sector.

Based on their suggestions, a roadmap is being prepared to address issues related to duty structure for the petrochemical value chain, impact of Foreign Trade Agreements (FTAs), Technology upgradation, Imparting Skills to Manpower, Plastic Waste Management, Standardization of plastic products, Plastic Processing Machinery etc.

Establishment of Plastic Parks

At present the Government has accorded

गत 8 वर्षों की सीमांत लाभ अर्जित कर रही है। नए कृषि रसायनों के उत्पादन एवं विपणन के लिए एचआईएल विभाग की ओर से 15 करोड़ रुपए की सहायता से पैंडिमिथालीन, ग्लाईफोसेट (टेक), होई प्यूरिटी डिकोफोल, सस्पेंसन कंस्ट्रेट (एससी) फार्मूलेशन प्लांट आदि संयंत्रों की स्थापना कर रहा है।

प्रमुख पेट्रोरसायन संघों के साथ परिसंघवाद तथा भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करना

माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने पेट्रोरसायन से संबंधित उद्योग संघों जैसे कैमिकल्स एंड पेट्रोकैमिकल्स मेन्यूफैकचरर्स एसोशिएसन (सीपीएमए), ऑल इंडिया प्लास्टिक मेन्यूफैकचरर्स एसोशिएसन (एआईपीएमए), आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई), एसोशिएसन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एसएफआई), ऑल इंडिया फ्लैट टेप मेन्यूफैकचरर्स एसोशिएसन (एआईएफटीएम), प्लास्टिक मशीनरी मेन्यूफैकचरर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया (पीएमएमएआई) के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई।

उनके सुझाावों के आधार पर पेट्रोरसायन मूल्य श्रृंखला के लिए शुल्क संरचना, विदेशी व्यापार समझौता (एमटीए) का प्रभाव, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कुशल जनशक्ति, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक उत्पादों का मानकीकरण आदि से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है।

प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

वर्तमान में सरकार ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम

approval for setting up plastic parks in Madhya Pradesh, Odisha, Assam and Tamil Nadu. However, in view of demand from other State Governments i.e. Uttar Pradesh, Haryana, Kerala, Gujarat etc., the Department has proposed to increase the number of plastic parks to be setup from 4 to 10.

Skill Development

Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET) will impart Skill Development/ Vocational training to around 42,500 students in 2014-15 to meet the demand for skilled manpower from plastic and allied industries of which 20391 persons have already been trained. CIPET has already signed MoUs with some State Governments in this regard. The placement of the trained students from CIPET is almost 100%. There is a huge demand across the Country for more centres of CIPET, and the Ministry has decided to set up 10 additional centres including 4 vocational training centres.

Research & Development

- In order to encourage the plastics industries under 'Make-in India' campaign, initiative has been taken for "Standardization of Plastic Products". In a meeting in the

एवं तमिलनाडु में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया है। तथापि, अन्य राज्य सरकारों से उठती मांग को देखते हुए अन्य राज्य सरकारों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात आदि की मांग को देखते हुए विभाग ने प्लास्टिक पार्कों की संख्या 4 से बढ़ाकर 10 करने का प्रस्ताव किया है।

कौशल विकास

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी (सिपेट) वर्ष 2014–15 के दौरान 42,500 छात्रों को कौशल विकास/रोजगार–परक प्रशिक्षण देगा ताकि प्लास्टिक एवं सहायक उद्योगों से कुशल जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके जिसमें 20391 व्यक्तियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सिपेट ने कुछ राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए हैं। सिपेट से प्रशिक्षित छात्रों का प्लेसमेंट लगभग 100 प्रतिशत है। सिपेट के और अधिक केंद्रों के लिए देश भर में भारी मांग हो रही है और मंत्रालय ने 4 रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण केंद्रों सहित 10 अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अनुसंधान एवं विकास

- ''मेक इन इंडिया'' अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादों के मानकीकरण का कार्य शुरू किया गया है। 11 नवंबर, 2014 को मंत्रालय ने एक बैठक में प्लास्टिक एवं

Ministry on 11th November, 2014, it was proposed to pursue BIS to promote more standards by creating a dedicated Divisional Council on plastics and allied products.

- CIPET has signed MoUs with Moscow State University, Russia for faculty and student exchange programmes and collaboration in the area of R&D in Polymers and nano materials
- MoU has been signed between CIPET and SABIC Technology Centre for joint collaborative research work of mutual interest through Ph.D programmes to be supported by SABIC.

Rationalization of customs duty structures

In the Budget 2014-2015 announced on 10th July 2014, Government approved the long pending rationalization of customs duty structures which will increase competitiveness of the domestic petrochemical industry to meet global challenges. The major announcements made which will boost investment by domestic industry are:

- Customs duty reduction on petrochemical feedstocks namely ethane, propane and reformate to 2.5%.

सहयोगी उत्पादों से संबंधित समर्पित प्रभागीय परिषद के सृजन के द्वारा मानकों को सवंर्द्धित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से संपर्क करने का प्रस्ताव किया गया था।

- सिपेट मास्को स्टेट विश्वविद्यालय, रूस के साथ संकाय एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम तथा पॉलीमर एवं नैनोमैटेरियल के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए सहयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सिपेट और एसएबीआईसी टेक्नोलोजी सेंटर, के साथ संयुक्त रूप से सहयोगी अनुसंधान कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि एसएबीआईसी के सहयोग से पीएचडी कार्यक्रम के माध्यम से परस्पर रुचिपूर्ण क्षेत्र में संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य किया जा सके।

सीमा शुल्क अवसंरचना में युक्तिकरण

वर्ष 2014–15 के बजट में, जोकि 10 जुलाई, 2014 को घोषित की गई थी, में सरकार ने घरेलू पेट्रोरसायन उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु लंबे समय से लंबित सीमा शुल्क अवसंरचना के युक्तिकरण की मांग को अनुमोदित कर दिया। घरेलू उद्योग में निवेश को बढ़ाने के लिए प्रमुख घोषणाएं निम्नानुसार है:

- पेट्रोरसायन फीडस्टॉक जैसे ईथेन, प्रोपेन एवं रिफॉर्मेट पर सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत तक घटाना।

- Customs duty reduction on building blocks namely ethylene, propylene, butadiene and Ortho-Xylene.
- To sustain the recent investment on Spandex Yarn, an import substitution product, the customs duty on
- To remove the hardships faced by the domestic polystyrene manufacturers due to cheap imports from Singapore the polymer has been removed from the purview of India Singapore Free Trade Agreement.

CORCON-2014 - a programme supported by the Ministry was organized at Mumbai during 12 to 15 November, 2014. This event which provided a platform where various stake holders could discuss developments and improvements in corrosion control and mitigation attracted participation from academia and industry from across the globe.

A Seminar on **Green Chemistry and Engineering** was held on 16th October 2014 at Ankaleshwar, Gujarat. This was jointly organized by Green Chemistry Foundation and Indian Chemical Council with support from Ministry, Gujarat Pollution Control Board, and others. The event was organized with a view to impart understanding on 12 Principles of Green Chemistry and Green Engineering particularly amongst the Plant and Production Managers and to bring forth technical know-how of implementing Green Chemistry and Green Engineering practices with a profit-centric approach.

- बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ईथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाडीन एवं ओर्थो–जाइलीन पर सीमा शुल्क को घटाना।
- आयात प्रतिस्थापन उत्पाद स्पेंडेक्स यार्न पर हालिया निवेश को बनाए रखना तथा इसके विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत तक घटाना।
- घरेलू पॉलीस्टाइरिन विनिर्माताओं की समस्याओं, जोकि मुख्यतः सिंगापुर से सस्ते आयात के कारण है, को दूर करने के लिए भारत सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौते की परिधि से पॉलीमर को बाहर करना।

कोरकोन–2014– कार्यक्रम का आयोजन मंत्रालय के सहयोग से मुंबई में 12 से 15 नवंबर, 2014 तक आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने विभिन्न पणधारकों को जंग नियंत्रण एवं शमन के क्षेत्र में विकास एवं सुधार पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया जिसमें विश्व भर से शिक्षाविदों एवं उद्योगों ने भागीदारी की।

हरित रसायन एवं इंजीनियरिंग विषय पर एक सेमिनार 16 अक्टूबर, 2014 को अंकालेश्वर, गुजरात में आयोजित किया गया था। यह आयोजन हरित रसायन फाउंडेशन एवं भारतीय रसायन परिषद द्वारा मंत्रालय, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस आयोजन का लक्ष्य हरित रसायन एवं हरित इंजीनियरिंग के 12 सिद्धांतों को समझने खासतौर पर संयंत्र एवं उत्पादन प्रबंधकों को समझाने तथा हरित रसायन एवं हरित इंजीनियरिंग की परंपरा को लाभ केंद्र एप्रोच के साथ क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी जानकारी देना था।

Initiatives under Digital India

Web based application for import and export of chemicals – The Ministry is going to develop a web-based application that will aid in Import and Export of chemicals. While different chemicals are imported or exported to various countries across the globe, in the European Union region, the registration of chemicals and companies is mandatory before any imports are allowed. Export companies also have to provide information such as chemical composition, concentration, level of purity or impurity and quantity of chemicals that have to be traded.

डिजिटल भारत के अधीन पहलें

रसायनों के आयात एवं निर्यात के संबंध में वेब आधारित एप्लीकेशन– मंत्रालय रसायनों के आयात एवं निर्यात के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन का विकास करने जा रहा है। विभिन्न प्रकार के रसायन का आयात एवं निर्यात विश्व भर के विभिन्न देशों से किया जाता है जबकि यूरोपियन यूनियन क्षेत्र में किसी प्रकार के आयात से पहले रसायनों एवं कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य है। निर्यात कंपनियों को भी रसायन संघटकों, घनत्व, शुद्धता एवं अशुद्धता का स्तर तथा रसायनों की मात्रा, जिसका व्यापार करना है, के संबंध में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

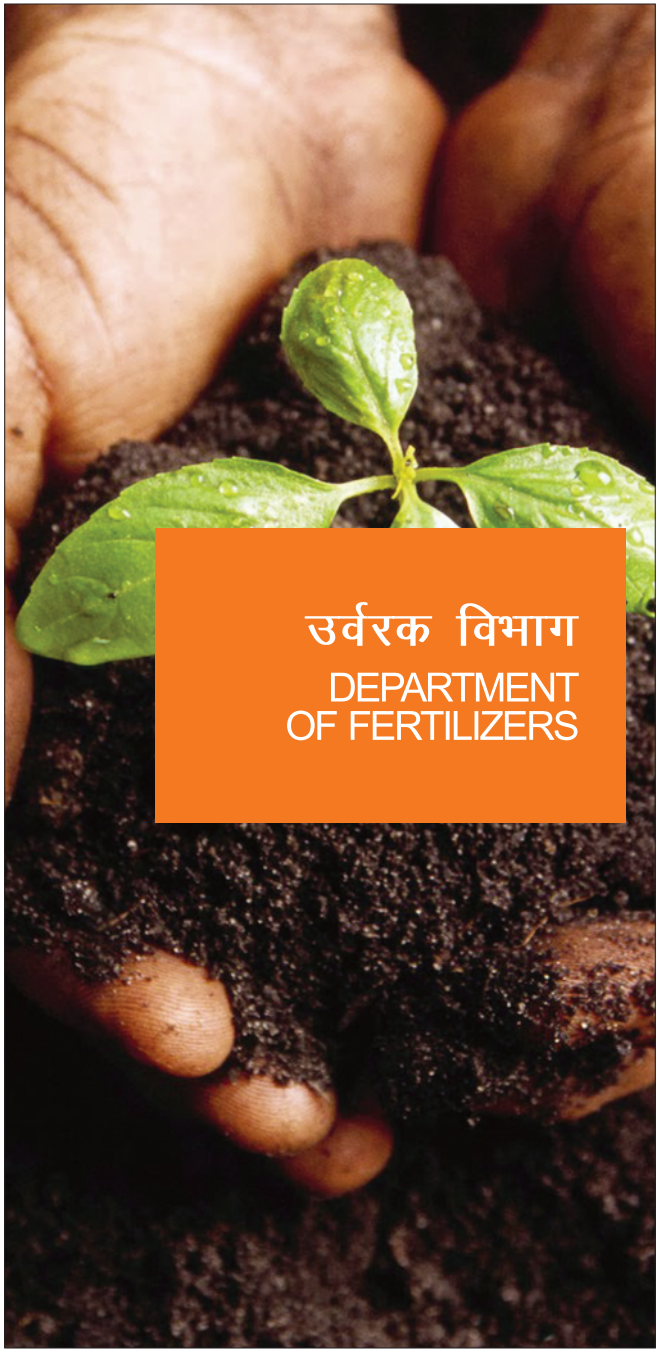
उर्वरक विभाग
DEPARTMENT
OF FERTILIZERS

Initiatives under "Make in India"

Domestic Production of Urea and NPK Fertilizers– Domestic Production during the last ten years was severely curtailed due to lack of initiative. Under the NDA Government, the following initiatives have been taken to ramp up production, and building capacity in domestic manufacturing of Urea & NPK Fertilizers.

- The Ministry is closely interacting with domestic producers on a regular basis and immediately addresses issues regarding the problems faced by them to ensure that they are able to maximize their production capacities. The chart below reflects how the initiatives of the Ministry have resulted in robust domestic production capacity utilization.

Urea Production June-Nov. 2014	Production Quantity	Capacity Utilization
Public sector	35.37 LMT	112.1%
Co-operative Sector	32.39 LMT	122.9%
Private Sector	47.05 LMT	104.3%
Complex Fertilizers – NPK		
Public sector	6.80 LMT	62.9%
Co-operative Sector	10.94 LMT	133.8%
Private Sector	2.27 LMT	137.8%

"Make in India" – Revival Initiative

- To pursue self-reliance in the

"मेक इन इंडिया" के तहत पहल

यूरिया एवं एनपीके उर्वरकों का घरेलू उत्पादनः– घरेलू उत्पादन पहल के अभाव में पिछले 10 वर्षों में बहुत ही कम रहा था। एनडीए सरकार के तहत, यूरिया एवं एनपीके उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में उत्पादन को बढ़ाने और क्षमता विकसित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गईं हैं :–

- मंत्रालय घरेलू उत्पादकों से नियमित आधार पर संपर्क करता रहता है और उनके सामने आ रही समस्याओं का तत्काल निपटान यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे अपनी उत्पादन क्षमता को अधिक–से–अधिक बढ़ाने में सफल हों। नीचे दिया गया चार्ट यह दर्शाता है कि किस प्रकार सुदृढ़ घरेलू उत्पादन क्षमता उपयोग में मंत्रालय की पहलों का परिणाम आया हैः–

यूरिया उत्पादन जून–नवंबर, 2014	उत्पादन मात्रा	क्षमता उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्र	35.37 लाख मी.टन	112.1%
सहकारी क्षेत्र	32.39 लाख मी.टन	122.9%
निजी क्षेत्र	47.05 लाख मी.टन	104.3%
मिश्रित उर्वरक –एनपीके		
सार्वजनिक क्षेत्र	6.80 लाख मी.टन	62.9%
सहकारी क्षेत्र	10.94 लाख मी.टन	133.8%
निजी क्षेत्र	2.27 लाख मी.टन	137.8%

''मेक इन इंडिया'' – पुनरुद्धार पहल

- घरेलू उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त

Domestic Fertilizer production, the Ministry has fast-tracked the Revival of the Fertilizer Units at Gorakhpur, Sindri, Barauni, Talcher, and Ramagundam, and also committed to the revival of the Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT) and restructuring of Madras Fertilizers Limited (MFL).

JVAs to revive fertilizer plant at Talcher

In a significant step towards augmenting the domestic urea capacity, four PSUs - GAIL (India) Limited, Coal India Limited (CIL), Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) and Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) - signed Joint Ventures Agreements (JVA) to set up an Integrated Coal Gasificatio cum Fertilizer and Ammonium Nitrate complex at Talcher in Odisha.

Talcher Chemicals & Fertilizers Limited, shall be led by RCF and will be primarily responsible for setting up Ammonia-Urea, Nitric Acid-Ammonium Nitrate plants at an estimated investment of Rs 6000 Cr with majority stake held by RCF & CIL.

The Revival of the Talcher Unit of the FCIL is a path-breaking Alternative Fuel Strategy which is going to revolutionize Urea Manufacturing in India.

- The Ramagundam Unit is also being revived through the formation of Joint Venture and the proposal is in its final stages before commencement.

करने लिए मंत्रालय द्वारा गोरखपुर, सिन्दरी, बरौनी, तलचर और रामागुंडम में स्थित उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार में तेजी लाई है और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रांवनकोर लिमिटेड (फैक्ट) के पुनरुद्धार और मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) के पुनर्गठन के लिए भी प्रतिबद्ध है।

तलचर में उर्वरक संयंत्र के पुनरूद्धार के लिए संयुक्त उद्यम करार

घरेलू यूरिया क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम–गेल (इंडिया) लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ), फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ने उड़ीसा के तलचर में समेकित कोल गैसीकरण सह उर्वरक एवं अमोनिया नाइट्रेट परिसर की स्थापना करने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार (जीवीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

तलचर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफ के नेतृत्व में रहेगा जो 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित निवेश से अमोनिया–यूरिया, नाइट्रिक एसिड–अमोनिया नाइट्रेट संयंत्रों की स्थापना के लिए मुख्य से रूप जिम्मेदार होगा तथा आरसीएफ और सीआईएल की प्रमुख भागीदारी होगी।

एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार एक बेजोड़ वैकल्पिक ईंधन कार्यनीति है जो भारत में यूरिया क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रही है।

- रामागुंडम इकाई का पुनरुद्धार भी संयुक्त उद्यम के जरिये किया जा रहा है और इसमें चालू होने से पहले प्रस्ताव अपने अंतिम चरण में है।

- The FCI Aravali Gypsum and Mineral India Limited (FAGMIL) is setting up a SSP plant of 2,40,000 MT per annum capacity in Chittorgarh District of Rajasthan

The Amendment to the New Investment Policy was notified by the Ministry on 07.10.2014 to facilitate fresh investment in the Urea Sector with the purpose of making India self-sufficient in Urea. The Ministry has received 12 Proposals in this regard.

- द एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड (फैगमिल) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 2,40,000 मी. टन प्रतिवर्ष क्षमता का एसएसपी संयंत्र स्थापित कर रहा है।

यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा नए निवेश को सुकर बनाने के लिए 07.10.2014 को नई निवेश नीति में संशोधन अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में मंत्रालय को 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

औषध विभाग
DEPARTMENT OF
PHARMACEUTICALS

Prices of more Life Saving Drugs reduced

When the NDA Government took charge in May, 2014, under the leadership of the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, there were 440 drugs under Price Control under the DPCO. In 218 days 251 more drugs have been brought under the Price Control.

Out of these new drugs that have been brought under the Price Control, 47 drugs are for cancer, 22 Drugs are for Diabetes, 19 Drugs are for AIDS, and 84 Drugs are related to Cardio-vascular treatment.

This has benefited the public to the tune of approximately around Rs.558 crores.

The Integrated Pharmaceutical Database Management System has been launched by the Ministry where Pharmaceutical manufacturers are required to file all relevant data regarding their Drugs related to quality, quantity, strength, price, etc., on a quarterly basis. These parameters are monitored by the Ministry on a real-time basis to ensure greater transparency. As on date around 600 Companies are filing the details of their Drugs under this System which consists of almost 96% of the Pharma Industry in India.

The Ministry is also closely regulating and ensuring compliance of the Drugs Prices – 592 cases of overcharging were identified and process for recovery of the overcharged amount has been initiated.

अधिकांश जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में कमी

जब मई, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली तो उस समय डीपीसीओ के अंतर्गत 440 औषधियां मूल्य नियंत्रण के अधीन थीं। 218 दिनों में 251 औषधियों को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है।

इन नई औषधियों, जिन्हें मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है, में कैंसर की 47 औषधियां, मधुमेह की 22 औषधियां, एड्स की 19 औषधियां और 84 औषधियां हृदय रोग के उपचार से संबंधित हैं।

इससे जनता को लगभग 558 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है।

मंत्रालय द्वारा समेकित औषध डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आईपीडीएमएस) शुरू की गई है जहां औषध विनिर्माताओं के लिए त्रैमासिक आधार पर गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, मूल्य आदि के संबंध में अपनी औषधियों से संबंधित सभी प्रकार का संगत डाटा दर्ज करना अपेक्षित है। मंत्रालय द्वारा इन मापदण्डों की अधिक जबावदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर मॉनीटिरिंग की जाती है। आज की तिथि के अनुसार लगभग 600 कंपनियां इस प्रणाली के अंतर्गत अपनी औषधियों के ब्यौरे दर्ज कर रही हैं जो भारत में औषध उद्योग का करीब 96% है।

मंत्रालय दवा मूल्यों का बड़ी ही गंभीरता से विनियमन तथा अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है– अधिक मूल्य लेने के 592 मामले प्रकाश में आये हैं और अधिक वसूली गई धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

The Ministry has issued demand notices for Rs. 252.50 crores, for the overcharged amount along with the interest thereon from 01.06.2014 to 30.11.2014.

Jan Aushadhi Scheme

Branded medicines are sold by Drug manufactuer s at higher prices than their unbranded generic equivalents, which are as good in therapeutic value. Therefore, if generic medicines are made more accessible and available in the market, everyone would benefit. Jan Aushadhi Stores where, unbranded quality generic medicines are available at lower prices fulfil the large demand for quality medicines at affordable prices for the poor.

The Ministry has decided to implement the Jan Aushadhi Scheme on large scale covering all the districts in the country. Action under the new Business Plan undertaken by the Ministry has been initiated inviting EoIs from various individuals and organisations throughout the country to open the Jan Aushadhi Stores. Around 180 Drugs have been made available at the Jan Aushadhi Stores. Rate contract has been finalized for 249 drugs, while for 20 drugs the rate contracts are under finalization.

The Ministry has communicated to all State Governments to avail of this opportunity of providing affordable Drugs

मंत्रालय ने 01.06.2014 से 30.11.2014 के लिए ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि के लिए रूपये 252.50 करोड़ हेतु मांग नोटिस जारी की है।

जन औषधि स्कीम

औषध विनिर्माताओं द्वारा ब्रांडेड दवाएं उनके ब्रांड रहित जेनरिक समतुल्य दवाओं से अधिक मूल्यों पर बेची जाती हैं जो चिकित्सीय महत्व में उतनी ही अच्छी हैं। इसलिए, यदि जेनरिक दवाओं की बाजार में अधिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है तो इससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा। जन औषधि स्टोर जिनमें ब्रांड रहित गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाएं निम्नतर मूल्यों पर उपलब्ध हैं, गरीबों के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाओं की एक बड़ी मांग को पूरा करते हैं।

मंत्रालय ने देश में सभी जिलों को कवर करते हुए एक बड़े पैमाने पर जन औषधि स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। जन औषधि स्टोर खोलने के लिए देशभर में विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से हित अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने के लिए मंत्रालय द्वारा नई कारोबार योजना के अधीन कार्रवाई शुरू की गई। औषधियों के लिए स्टोरों में लगभग 180 औषधियां उपलब्ध की गई हैं। 249 औषधियों के लिए दर संविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है जबकि 20 औषधियों के लिए दर संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वे प्रत्येक जिला अस्पताल में जन औषधि बिक्री केंद्र खोल कर गरीबों को वहनीय

to the poor through opening of the Jan Aushadhi outlets in every District Hospital.

National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) is the first National level institute in Pharmaceutical Sciences with a proclaimed objective of becoming a centre of excellence for advanced studies and research in Pharmaceutical Science. The Government of India has declared NIPER as an "Institute of National Importance". It is an autonomous body set up under the aegis of the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India. The institute is conceived to provided leadership in pharmaceutical sciences and related areas not only within the Country, but also to the Countries in South East Asia, South Asia and Africa. NIPER is a member of Association of Indian Universities and Association of Commonwealth Universities. The vision of NIPER is to become a globally recognized brand in the areas of education and research in pharmaceutical sciences for the benefit of people of India and other countries and the growth of the pharmaceutical industry.

The Institute has so far filed 170 patents, out of which 36 are Indian granted patents and 14 have been filed internationally. Seven (07) technologies have been licenced out till date to various pharmaceutical companies and they are at various stages of development and

मूल्यों पर औषधियां प्रदान करने के इस अवसर का लाभ उठाएं।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) औषध विज्ञान में उन्नत अध्ययनों और अनुसंधान के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र बनने के उद्घोषित उद्देश्य के साथ औषध विज्ञान में प्रथम राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। भारत सरकार ने नाईपर को एक ''राष्ट्रीय महत्व के संस्थान'' के रूप में घोषित किया है। यह औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इस संस्थान द्वारा देश के अंदर ही नहीं अपितु दक्षिण–पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए भी औषध विज्ञानों और संबद्ध क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। नाईपर भारतीय विश्वविद्यालय संघ और राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ का एक सदस्य है। नाईपर का विजन भारत और अन्य देशों के लोगों के लाभ के लिए और औषध उद्योग की वृद्धि के लिए औषध विज्ञानों में शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में वैश्विक आधार पर मान्यता प्राप्त ब्रांड बनने का है।

संस्थान ने अब तक 170 पेटेंट दर्ज किए हैं जिनमें से 36 भारत द्वारा प्रदत्त पेटेंट हैं और 14 पेटेंट अंतर्राष्ट्रीय रूप से दर्ज किए गए हैं। विभिन्न औषधीय कंपनियों को अब तक सात (07) प्रौद्योगिकियों के लाइसेंस दिए गए हैं और वे विकास और वाणिज्यीकरण

commercialization.

- Composition and methods trapping an in activating pathogenic microbes and spematozos
- Protective agents as dimer of mandelic acid or a dimer of substituted mandelic acid
- An improved one-pot synthesis of pyridynyimethanone, a mefloquine intermediate for malaria
- An efficient process for racemization of clopidogrel
- Quick disintegrating taste masked composition
- Pharmaceutical compostion for enhancing anti-cancer efficacy of Tamoxifen
- A novel one step (NanoCrySp technology) process for the preparation of nano crystalline solid dispersions

There are three more novel lead technologies available with NIPER, Mohali which are at various stages of early development at the Institute and are listed below:-

- ETS-1 Identifying RNA APTAMER as a cancer therapeutics
- Recombinant Human Paraoxonase 1 enzymes method of generation and uses thereof

की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

- रोगाणुओं और स्परमैटोज को निष्क्रिय बनाने के लिए संयोजन और विधियां।
- मेंडेलिक एसिड के डिमर अथवा एवजी मेंडेलिक एसिड के डिमर रूप में संरक्षी कारक।
- पायरीडायनीइमेथानोन जो मलेरिया के लिए एक मैफ्लोक्वीन मध्यवर्ती है का एक बेहतर वन–पॉट संश्लेषण।
- क्लोपोडोग्रेल के रेसेमाइजेशन के लिए एक दक्ष प्रक्रिया।
- द्रुत स्वाद विखण्डन का अप्रत्यक्ष संयोजन।
- टेमॉक्सीफेन की कैंसररोधी प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए औषधीय संयोजन।
- नैनो क्रिस्टेलाइन सॉलिड विसर्जन प्रक्रिया को तैयार करने के लिए एक नई एकस्तरीय (नैनो क्राईएसपी प्रौद्योगिकी)।

नाईपर, मोहाली में तीन और नव उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं जो संस्थान में प्रारम्भिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और नीचे सूचीबद्ध हैं:

- कैंसर थिरेप्यूटिक्स के रूप में आरएनए एपीटीएएमईआर की पहचान करने के लिए ईटीएस–1
- जनरेशन और उसके उपयोग की रिकम्बीनेंट हयूमन पैराऑक्सोनेस 1 एंजाइम विधि

- Recombinant SSOPOX enzymes, method of generation and reusable nanobiocatalyst of same

Apart from above, a dozen of small molecules (NCE's) are in various stages of pre-clinical development in the following therapeutic areas:-

- Anti-infectives (Malaria, TB, Leishmaniasis)
- Anti-virals
- Lifestyle diseases
- Two newly isolated pure compounds from natural products / botanicals are in pre-clinical development stage as anti-cancer agents

"Make in India"

The Ministry has launched major measures to encourage production and capacity-building in the Pharma Sector

Cluster Development Programme for Pharma Sector (CDS-PS) - With a vision to catalyze and encourage quality, productivity and innovation in the pharmaceutical sector to meet the ever growing domestic needs, and at the same time, enable the Indian pharmaceutical sector to play a leading role in a competitive global market, the Ministry has approved the introduction of CDS-PS on 27.10.2014.

- रिकम्बीनेंट एसएसओपीओएक्स एंजाइम, उसके जनरेशन और पुनः इस्तेमाल होने वाले नैनोबायोकैटालिस्ट की विधि।

उपर्युक्त के अलावा निम्ननिखित चिकित्सीय क्षेत्रों में दर्जन भर लघु मौलिक्यूल (एनसीई) पूर्व नैदानिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं–

- एंटी–इनफैक्टिव्स (मलेरिया, क्षय रोग, लीषमैनियासिस)
- एंटी–वायरल
- जीवनशैली रोग
- प्राकृतिक उत्पादों/वनस्पति से दो नए पृथक किए गए शुद्ध सम्मिश्रण कैंसररोधी कारकों के रूप में पूर्व–नैदानिक विकास की अवस्था में हैं

''मेक इन इंडिया''

मंत्रालय ने औषध क्षेत्र में उत्पादन और क्षमता विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उपाय शुरू किए हैं।

औषध क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीएस–पीएस)– हमेशा से बढ़ती हुई घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही प्रतिस्पर्द्धी वैश्विक बाजार में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारत को औषध क्षेत्र में सक्षम बनाने हेतु गुणवत्ता, उत्पादकता और नवोन्मेष को उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करने के विजन के साथ मंत्रालय ने दिनांक 27.10.2014 को सीडीएस–पीएस की शुरूआत करने का अनुमोदन कर दिया है।

Task Force have been set up, comprising of representatives from Government Departments/ Institutions and Industry Associations has been set up in the Ministry to enable the Private Sector to lead the growth of Pharmaceutical Sector and for Development of manufacturing capabilities in each medical vertical in Pharmaceutical production.

For the first time a Task Force has also been set up to identify issues relating to the promotion of domestic production of high end Medical Devices and Pharmaceutical Manufacturing Equipment in the Country.

The National Centre for Research and Development in Bulk Drug (NCRDBD) at NIPER, Hyderabad, is proposed to become an innovation R&D provider in the field of bulk drugs in offering competitive processes. This Centre will also provide centralized Research facilities and technologies, analytical facilities and consulting services for process improvement and optimization. A special emphasis is given to empowerment of MSME sector.

Revival Initiatives for Pharma PSUs – The Ministry has initiated Rehabilitation Schemes for two sick CPSEs - Hindustan Antibiotics Ltd. and Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. Another sick unit – Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd has reported a 243% increase in production during the period April-October, 2014, as compared to last year

कार्यबल गठित किए गए हैं जिनमें सरकारी विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं और मंत्रालय में निम्नलिखित के लिए उद्योग संघों का गठन किया गया है।

निजी क्षेत्र को औषध क्षेत्र की वृद्धि में अगुवाई करने में सक्षम बनाना और औषध उत्पादन में प्रत्येक चिकित्सा वर्टिकल में विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना।

पहली बार देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा साधनों और औषध विनिर्माण उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए एक कार्यबल का भी गठन किया गया है।

नाईपर, हैदराबाद में राष्ट्रीय बल्क औषध अनुसंधान एवं विकास केंद्र (एनसीआरडीबीडी) को प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रियाएं प्रदान करने में बल्क औषधियों के क्षेत्र में एक नवोन्मेष अनुसंधान और विकास प्रदाता बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र केंद्रीकृत अनुसंधान सुविधाएं और प्रौद्योगिकियां, विश्लेषणात्मक सुविधाएं और प्रक्रिया सुधार तथा इष्टतमीकरण के लिए परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करेगा। एमएसएमई क्षेत्र के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है।

औषध पीएसयूज के लिए पुनरुद्धार पहलें – मंत्रालय ने दो रुग्ण सीपीएसयूज – हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के लिए पुनर्वास स्कीमें शुरू की हैं। एक अन्य रुग्ण यूनिट–बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल–अक्टूबर, 2014 की अवधि के दौरान उत्पादन में 243 प्रतिशत की वृद्धि

– from Rs.11.23 crores to Rs. 38.62 crores.

General Initiatives of the Ministry

"Swachh Bharat Abhiyan"

The "Swachh Bharat Abhiyan" was enthusiastically taken up in all Departments, Organisations and Public Sector Undertakings under the administrative control of the Ministry from 25th September 2014. A personal message from the Hon'ble Minister was sent to all officers and employees exhorting them to realize the dream of the Mahatma Gandhi ji for a "Clean India". In order to bring awareness among the employees and their family members, the Minister and all senior officials of the Ministry personally participated in the cleanliness drive.

Posters, Mailers, Bulletins explaining the importance of cleanliness, and the steps to be taken to achieve it were prominently and widely circulated. A number of organisations are playing the pre-recorded message of the "Swachh Bharat Abhiyan" on their helplines and telephone lines.

सूचित की है जो 11.23 करोड़ रुपए से बढ़कर 38.62 करोड़ रुपए हो गया है।

मंत्रालय की सामान्य पहलें

''स्वच्छ भारत अभियान''

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बड़े ही उत्साह से 25 सितम्बर, 2014 से ''स्वच्छ भारत अभियान'' की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी जी के ''स्वच्छ भारत' की कल्पना को साकार करने के लिए माननीय मंत्री महोदय की तरफ से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए एक व्यक्तिगत संदेश भेजा गया। सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के मध्य जागरुकता उत्पन्न करने के लिए मंत्री तथा मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वच्छता अभियान में व्यक्तिगत रूप से भाग लिए।

स्वच्छता के महत्व का उल्लेख करने वाले पोस्टर, मेलर्स, बुलेटिन्स और इसको प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों को बहुत ही यथेष्ठ तथा विस्तृत ढंग से परिचालित किया गया। बहुत से संगठन अपने हेल्पलाइन एवं अपने टेलीफोन लाइनों पर ''स्वच्छ भारत अभियान'' के प्री–रिकार्डेड संदेश को प्रसारित कर रहे हैं।

Green India

A grid rooftop Solar Power Plant of 100KW at the roof of the NFL's Corporate Office at NOIDA. This power is being utilized internally by NFL.

RCF is setting up new Sewage Treatment Plant at its Trombay unit which will treat 22.75 MLD Sewage per day at a cost of about Rs. 200 crore. The said project, when goes on-stream, will generate 15 MLD of treated water for usage in plant operation in RCF and BPCL thereby saving fresh water intake to that extent which will benefit about 30,000 families in the city of Mumbai. This will also bring down pollution, as under normal course, the Municipality discharges this sewage into the sea with minimal mandatory treatment.

RCF has been actively engaged in a massive drive for tree plantation under "Chembur Green Project", launched to establish greenery in the eastern suburb of Mumbai. To develop the green belt further, the Company is undertaking the task of planting 10000 trees this year.

ग्रीन इंडिया

एनएफएल के नोएडा स्थित कार्पोरेट कार्यालय की छत पर 100 किलोवाट का ग्रिड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट लगाया गया है। इसके द्वारा उत्पादित बिजली को एनएफएल द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है।

आरसीएफ अपनी ट्राम्बे इकाई में एक नए मल–जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर रहा है जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिदिन 22.75 एमएलडी मल–जल का उपचार किया जाएगा। उक्त परियोजना जब लागू होगी तो यह आरसीएफ और बीपीसीएल में संयंत्र प्रचालन के उपयोग के लिए 15 एमएलडी उपचारित जल पैदा करेगी जिससे उस सीमा तक ताजे जल की बचत होगी जिससे मुंबई शहर में लगभग 30,000 परिवारों को फायदा पहुंचेगा। इससे प्रदूषण भी कम होगा क्योंकि सामान्य प्रक्रिया के तहत नगरपालिका इस मल–जल को न्यूनतम अनिवार्य उपचार करने के बाद समुद्र में बहा देती है।

आरसीएफ, मुंबई की पूर्वी उप–नगरी में हरियाली बनाए रखने के लिए चालू किए गए ''चेम्बूर हरित परियोजना'' के तहत वृक्षारोपण के बृहत अभियान में सक्रियता से लगा हुआ है। हरित पट्टी को विकसित करने के लिए कंपनी इस वर्ष 10,000 वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया है।

नाईपर मोहाली, चंडीगढ़
NIPER Mohali, Chandigarh

नांगल संयन्त्र, एनएफएल, पंजाब
Nangal Plant, NFL, Punjab

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Government of India

www.chemicals.nic.in
www.fert.nic.in
www.pharmaceuticals.gov.in